

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्श,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 20 नवम्बर, 2006

विषय: मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय में ओक पार्क स्थित मा० न्यायमूर्ति श्री काण्डपाल जी के आवास के नाली में ग्रेटिंग लगाने व अन्य मरम्मत(सिविल व विद्युतिकरण) के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2550/UHC/Admin.B/Const/2006, दिनांक 28.9.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय में ओक पार्क स्थित मा० न्यायमूर्ति श्री काण्डपाल जी के आवास के नाली में ग्रेटिंग लगाने व अन्य मरम्मत(सिविल व विद्युतिकरण) के कार्य हेतु रु० 3,45,000/- के आगपन के विरुद्ध टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत रु० 3,34,000/- (रुपये तीन लाख बीतीस हजार मात्र) की लागत के आगपन को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु० 3,34,000/- (रुपये तीन लाख बीतीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय किए जाने को भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल गिम्प शर्मा के अधीन सहर्ष प्रदान करने हैं :-

- (1) आगपन में उल्लिखित दरों का विरलेपण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूस ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा याजार भाव में ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगपन गणित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदुपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
- (4) एक मुरत प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगपन गणित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
- (5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पारित किया जाय ।
- (6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भूतली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जाय ।
- (7) आगपन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (8) कार्य कराने समय यह सुनिश्चित करले कि वार्षिक अनुरक्षण से सम्बन्धित नियमों एवं नार्मस में अधिक किसी भी स्थिति में व्यय न की जाय । इसका पूर्ण दायित्व कार्यकारी इकाई का होगा ।

- (9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय ।
- (10) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर चर्चेंज कलस, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निम्न आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशहसी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आय-व्यय की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत संस्था-शोर्षक "2014 न्याय प्रशासन-00-आयोजनेतर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-00-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा ।
- 3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के असासकीय संख्या-681/XXVI(5)/2006, दिनांक 16.11.06 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीया,

(इन्दिरा आरौप)

सचिव ।

संख्या-35-दो(2)/XXXVI(1)/2006-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निर्मालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महासंस्थाकार (संस्था एवं हकदारों), ओबराय बिल्डिंग, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. अधिशहसी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल ।
6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
7. एन०३एच०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)

अपर सचिव ।